श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)

संक्षिप्त ब्यौरा - Dated 14th February 2020

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) की शुरूआत विकास की दहलीज पर खड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक हस्तक्षेप करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 21 फरवरी, 2016 को की गई थी।

- **300 रूर्बन क्लस्टरों का समयबद्ध तरीके से विकास किया जाना परिकल्पित** है।
- पूरे देश में शहरीकरण के लक्षणों में वृद्धि - अर्थात जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, गैर-कृषि रोजगार का ऊंचा स्तर, बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों की मौजूदगी और अन्य सामाजिक आर्थिक मानकों को दर्शाने वाले ग्रामीण क्लस्टरों की पहचान की जाती है।
- इस मिशन का लक्ष्य स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि तथा सुनियोजित रूर्बन क्लस्टरों का सृजन करते हुए रूर्बन क्लस्टरों का कायाकल्प करना है।
- तालमेल और सीजीएफ संसाधनों के माध्यम से सरकार द्वारा अब तक अनुमोदित निवेशों का संक्षिप्त ब्यौरा तथा किया गया वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

चयनित क्लसटरों की संख्या	अनुमोदित एकीकृत क्लस्टर कार्य योजनाओं (आईसीएपी) की संख्या	अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की संख्या	नियोजन के लिए अधिसूचित क्लस्टरों की संख्या	अब तक जारी की गई निधियों का कुल केंद्रीय अंश
296	288	240	171	1,842.97 करोड़ रू.

- इस मिशन के तहत पूरे देश में विषयपरक आर्थिक विकास केंद्रों के साथ 288 रूर्बन क्लस्टरों (अनुमोदित आईसीएपी वाले) का विकास किया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण निधि अंतर (सीजीएफ) के रूप में प्रत्येक रूर्बन क्लस्टर के लिए अनुमानित निवेश का 30 प्रतिशत तक वित्तपोषण सहायता प्रदान की जाती है, जबकि निधियों का 70 प्रतिशत राज्यों द्वारा समन्वित राज्य और केंद्रीय कार्यक्रमों के साथ तालमेल के माध्यम से जुटाया जाता है।

288 आईसीएपी में अनुमोदित कुल निवेश			31 दिसम्बर, 2019 तक कुल व्यय (करोड़ रू. में)			% व्यय
तालमेल	सीजीएफ	कुल	तालमेल	सीजीएफ	कुल	
21,194	6,882	28,075	5619	1,070	6,689	27% (तालमेल) 16% (सीजीएफ) 24% (कुल)

- **अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य और उपलब्धियां:**

1. नियोजन और स्थापत्य कला तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली तथा सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदबाद के सहयोग से मॉडल भूमि उपयोग के लिए मॉडल दिशा-निर्देश, विकास नियंत्रण तथा रूर्बन क्लस्टों के लिए उचित प्रवर्तन तंत्र के साथ सेवा स्तरीय मानदंड तैयार किए गए हैं तथा भौगोलिक योजना के मसौदे पहले से तैयार करने वाले 6 राज्यों के साथ साझा किए गए हैं।
2. रूर्बनसॉफ्ट (मिशन का एमआईएस) को पुन: सशक्त करके आईसीएपी, डीपीआर अपलोड की गई हैं।
3. भुगतान में पारदर्शिता, दक्षता और कार्यसाधकता सुनिश्चित करने हेतु राज्यों से संबंधित विक्रेताओं/एजेंसियों को सीधे भुगतान करने के लिए रूर्बनसॉफ्ट को पीएफएसएस के साथ एकीकृत किया गया है। 10 राज्यों ने भुगतान के लिए पहले ही रूर्बनसॉफ्ट-पीएफएमएस प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है।
4. आईईसी प्रभाग द्वारा सफलता की कहानियों के संबंध वर्तमान में तीन फिल्में बनाई जा रही हैं।

- **<u>मौजूदा प्रमुख मुद्दे:</u>**

1. कार्यक्रम प्रभाग मिशन की वास्तविक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है ताकि प्रस्तावित दो वर्ष की विस्तारित अवधि के भीतर व्यय कर लिया जाए।

2. मंत्रालय के माह, नवम्बर के पत्र (एसआरडी द्वारा लिखे गए) के संबंध में सीईओ, नीति आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्युक्तियां -

   ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र की विषय-वस्तु –'रूर्बन क्लस्टरों की सफलता से सीखना, अगले तीन वर्षों में 1000 से अधिक क्लस्टरों के लिए विस्तारित कार्यक्रम'

   नीति आयोग की टिप्पणी : एसपीएमआरएम (इसके मूल्यांकन के संबंध में) की सफलता और कमजोरियों से सीखने के पश्चात, इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार उन्नयन किया जा सकता है।

3. **5वें सीआरएम की अभ्युक्तियां** –

   क. अच्छी प्रगति दर्शाने वाले क्लस्टर/क्लस्टरों में प्रारंभिक सकारात्मक परिणाम

ख. राज्यों ने और अधिक क्लस्टर आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है।

4. विभिन्न लक्ष्यों के संबंध में प्रगति

वास्तविक प्रगति	**आईसीएपी**	**डीपीआर**
वर्ष 2019-20 के संबंध में वार्षिक लक्ष्य	**272 से 300 तक प्रगति (शेष 28 आईसीएपी)**	**126 से 225 तक प्रगति (100 अन्य डीपीआर)**
जनवरी 2020 तक हुई प्रगति	**288 / 300**	**240 / 288**
शेष लक्ष्य को 31 मार्च, 2020 तक पूरा किए जाने की योजना	पश्चिम बंगाल से 7, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, अरूणाचल प्रदेश, तेलंगाना प्रत्येक से 1 31 मार्च के पश्चात किसी आईसीएपी का अनुमोदन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।	लंबित में से अधिकांश हैं : झारखंड से 13, असम से 8, पश्चिम बंगाल से 7, बिहार से 5
वित्तीय प्रगति	**जारी निधियां (केंद्रीय अंश)**	**राज्यों द्वारा व्यय**
2019-20 के लिए वार्षिक लक्ष्य	300 करोड़ रू. (संशोधित अनुमान)	1200 करोड़ रू. के सीजीएफ व्यय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
14th February 2020 तक की गई प्रगति	258 करोड़ रू.	1,071 करोड़ रू. (31 दिसम्बर तक)
शेष लक्ष्य को 31 मार्च, 2020 तक पूरा किए जाने की योजना	300 करोड़ रू. का लक्ष्य प्राप्त करेंगे	1200 करोड़ रू. से अधिक का लक्ष्य 31 मार्च तक प्राप्त किए जाने की संभावना है।